POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2021-23 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2023/अंक 05

मासिक प्रेषण दि. 8 मई, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 मई, 2023 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! पिछले दिनों देश के सतत् विकास के लिए ग्रामीण विकास के महत्व को देखते हुए भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा नई दिल्ली में समावेशी ग्रामीण विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में देश विदेश के प्रबुद्धजनों ने अपनी सक्रिय भागेदारी निभाई।

सम्मेलन में उभरकर सामने आया कि भारत में ग्रामीण विकास के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। ग्रामीण अर्थ व्यवस्था राष्ट्रीय आय में 46 फीसदी महत्वपूर्ण योगदान देती है। देश के सतत् विकास के लिए ग्रामीण भारत में उद्यमशीलता और रोजगार के लिए सक्षम समर्थन प्रणाली की आवश्यकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास के लिए भारत अपने संसाधनों और विशेषज्ञता का लाभ उठाकर ग्रामीण उद्यमशीलता और रोजगार के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत में युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों पर बहुत ध्यान दिया है। लेकिन अभी तक इसके वांछित परिणाम नहीं मिले हैं। भारत को एक आदर्श बदलाव करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूती देने की जरूरत है।

भारत को जी-20 की अध्यक्षता से भविष्य में कई क्षेत्रों में अच्छी कामयाबी दिखाई दे रही है। मसलन स्वास्थ सेवाएं, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, कृषि जैसे कई क्षेत्रों में देश का युवा वर्ग, शिक्षार्थी, महिलाएं सामूहिक भागीदारी से काम करने को तैयार है। इसमें हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। इससे रोजगार पाने की संभावना बढ़ेगी।

हर चुनौती एक अवसर प्रस्तुत करती है। इसके लिए 'जनजागरूकता' पैदा करना एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर सकता है। जरूरत है जन-जन की भागीदारी के लिए सामूहिक प्रयास....।

बच्चों के नवाचार से होंगे सपने साकार

स्कूली बच्चों के विचार (आइडिया) को सामने लाने और फिर उसे स्टार्टअप की शक्ल देने पर अब तेजी से काम होगा। सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग यूनिसेफ के साथ मिलकर ऐसे बच्चों की टीम तैयार कर रहा है। इसके लिए प्रदेश के हर जिले में दो लॉन्च पैड (इन्क्यूबेशन सेंटर का छोटा रूप) खोले जाएंगे। यहां बच्चें अपने आइडिया को लॉन्च कर सकेंगे और डीओआईटी उसे स्टार्टअप की शक्ल देने के लिए सहयोग करेगा।

फिलहाल 1800 से ज्यादा स्कूलों के 30 हजार बच्चों को इससे जोड़ने की मुहिम शुरू की गई है। नवाचार में रुचि रखने वाले बच्चों को लॉन्च पैड में बताएंगे कि किस तरह स्टार्टअप बन सकता है। यदि आपके पास कोई आइडिया है तो इन्क्यूबेशन सेंटर आपको गोद लेते हैं। आपके स्टार्टअप को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए भी जरूरी मदद की जाएगी।

महिलाएं गांवों को करेगी रोशन

देश के अलग-अलग राज्यों की ग्रामीण समुदाय की 15 महिलाओं ने जयपुर के हरमाड़ा गांव स्थित बेयरफुट कॉलेज इंटरनेशनल में पांच महीने का सौर ऊर्जा प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। ये महिलाएं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान सहित अन्य राज्यों से हैं।

हाल ही कॉलेज के एक समारोह में इन्हें सोलर इंजीनियर के रूप में स्नातक की उपाधि देकर सम्मानित किया गया है। प्राप्त किए गए कौशल से ये महिलाएं अब अपने-अपने राज्य के गांवों को रोशन करने का काम करेंगी। प्रशिक्षण प्राप्त ये महिलाएं आसानी से बिंदी सोलर टार्च, होम-लाइटिंग सिस्टम, सोलर एलईडी बल्ब आदि बनाकर उनका व्यवसाय कर सकेंगी। डिजिटल रूप से साक्षर ये महिलाएं भीम एप पर लेन-देन भी कर सकती हैं।

किसान कम पानी में उगाएगा फसल

जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय और भाभा परमाणु अनुसंधान (बार्क) मुंबई की ओर से किए जा रहे शोध से प्रदेश में कम पानी में भी खेती संभव हो सकेगी। विश्वविद्यालय और बार्क की ओर से उत्पादित हाइड्रोजेल उत्पाद से पश्चिमी राजस्थान में कम पानी से फसलों के उत्पादन पर काम किया जा रहा है।

आइड्रोजेल भूमि में पानी को सोखकर पौधों को उपलब्ध कराता है। यह अपने वजन से 400 गुना अधिक पानी को रोककर रखता है। विश्वविद्यालय ने गेहूं, जीरा, इसबगोल व सरसों के साथ सब्जियों में टमाटर पर प्रयोग किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। यह प्रयोग पश्चिमी राजस्थान में कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा।

राइट टू हेल्थ बिल-बड़ा चुनावी दांव

प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फोकस रहा है। उन्होंने मुफ्त दवा एवं जांच योजना, चिरंजीवी योजना में मुफ्त इलाज और अब स्वास्थ्य का अधिकार बिल लागू किया है।

मुख्य मंत्री ने चिकित्सकों की लंबी हड़ताल के बाद भी इसे लागू करने के लिए रास्ता निकाला, यह बड़ी बात है। प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उनका यह दांव कांग्रेस सरकार के लिए फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि, प्रदेश की आम जनता पर इस घोषणा को लेकर गहरा प्रभाव देखा गया है। लेकिन आगे चुनाव तक क्या स्थिति बनेगी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।

श्री योजना में 402 विद्यालय चयनित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत शिक्षक दिवस पर पीएम श्री योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इस योजना में पूरे देश में 14 हजार 597 सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है। इसमें राजस्थान के 402 विद्यालय शामिल है।

इन सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं जुटाई जाएंगी। देश के स्कूलों को मॉडल स्कूलों का दर्जा देने के लिए 27 हजार 860 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत किया गया है। इसमें से 60 प्रतिशत राशि केंद्र तथा 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करेगी। प्रत्येक स्कूल में दो से ढाई करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। इन स्कूलों को चयनित कर संस्था प्रधानों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे। योजना के तहत 2027 तक स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा।

सौभाग्य योजना में फर्जीवाड़ा?

प्रदेश के बांसवाड़ा जिले में केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना में 1.25 करोड़ रुपए के बिलों के भुगतान में फर्जीवाड़ा सामने आया है। मामला बागीदौरा-आनंदपुरी योजना के तहत गरीबों को मुफ्त बिजली कनेक्शन से जुड़ा है। जिसमें ठेकेदार ने कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी आधार नंबर दर्ज कर और फर्जी कनेक्शन दिखाते हुए भुगतान उठा लिया।

डिस्कॉम के अधिकारियों ने भी बिलों का भौतिक सत्यापन और अन्य जांचें किए बिना ही भुगतान कर दिया। गौरतलब है, कनेक्शन के लिए डिस्कॉम द्वारा केवल 649 मीटर दिए गए, लेकिन फर्म को भुगतान 1220 कनेक्शन का कर दिया। यानी जब मीटर ही नहीं मिले तो कनेक्शन कैसे हो गए? मामले की उच्चस्तरीय जांच आवश्यक है।

बंजर जमीन को बना दी हरितिमा ढाणी

चूरू जिले के सुजानगढ़ से सटे गांव गोपालपुरा की हरितिमा ढाणी बेहद अनूठी है। सरपंच सविता राठी और गांव की महिलाओं की जिद और जुनून ने सैकड़ों साल से उजाड़ पड़ी बंजर जमीन को टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। पिछले साल एक साथ एक दिन में यहां महिलाओं ने श्रमदान कर 5100 पौधे रोपे हैं।

यह ऐसी जगह है जहां राजस्थानी संस्कृति, परम्परा और संपदा को जिन्दा रखने की जिद की जा रही है। यह देखकर टूरिज्म डिपार्टमेंट भी इसे डेजर्ट पार्क की तर्ज पर विकसित करने को आगे आया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 30 लाख रुपए भी दिए हैं। अब यहां कैमल सफारी और ठेठ राजस्थानी खाने के व्यंजनों सहित लोक कलाकार तक पर्यटकों का मनोरंजन करते हैं। पर्यटकों के ठहरने के लिए झोंपड़ियां भी बनाई गई हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक भी आने लगे हैं।

मांगते-मांगते थक जाओगे...

चुनावी साल पर नजर रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई घोषणाएं की है। उन्होंने सबसे बड़े तोहफे के रूप में 19 नए जिलों और 3 संभागों की घोषणा करते हुए कहा कि बढ़ती जनसंख्या एवं बड़े क्षेत्रफल की वजह से सरकार व आमजन को नए जिलों की आवश्यकता महसूस हो रही थी।

उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में 50 जिले होने से प्रगति की गति दोगुनी होगी। एक बड़ा कदम उठाते हुए कांग्रेस सरकार ने नए जिले बनाए हैं। इससे जन भावना का सम्मान हुआ है। जनता के लिए आगे भी बचत, राहत और बढ़त का सिलसिला जारी रहेगा।

वसूला ग्रीन टैक्स, खर्च दूसरे कामों पर

प्रदेश में हरियाली बढ़ाने के लिए परिवहन विभाग ग्रीन टैक्स लगाकर जनता से हर साल करोड़ों रुपए वसूल रहा है, लेकिन यह पैसा सड़क, नाली, पुल व रोडवेज सहित कई निगमों का घाटा भरने में खर्च हो रहा है। पिछले पांच सालों में ग्रीन टैक्स से सरकार के खजाने में 11,186 लाख रुपए आए, लेकिन मात्र 51.43 करोड़ रुपए ही हरियाली बढ़ाने पर खर्च हुए।

लगातार बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए ग्रीन टैक्स लगाया गया, लेकिन हरियाली बढ़ाने वाले वन विभाग को इस टैक्स का पूरा पैसा नहीं मिल रहा। राशि के उपयोग का निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर होता है। यदि पूरा पैसा हरियाली बढ़ाने पर खर्च हो तो प्रदेश में कई नए पार्क विकसित हो सकते हैं।

मोटे अनाज से बन रहे कई उत्पाद

सदियों से राजस्थान में किसान जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी जैसे कई मोटे अनाज पैदा कर रहे हैं। मोटा अनाज यानी मिलेट पोषक तत्वों का खजाना माना जाता है। वर्ष 2023 अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित है। देश में बाजरा उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में पहले नंबर पर है। केंद्र व राज्य सरकार मोटे अनाज के उत्पादन को कई प्रकार से बढ़ावा दे रही है।

मोटा अनाज किसानों की तकदीर बदल सकता है। खेतों से निकलकर बाजरा दुनिया भर की भोजन की थालियों में पहुंच सकता है। मोटे अनाज से विभिन्न उत्पाद बनाने के लिए सरकार ने महिलाओं को ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की है।

बिना मिट्टी के भी उगेंगी सब्जियां

केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) ने हाइड्रोपोनिक्स खेती विकसित की है। खेती की इस आधुनिक पद्धति में बिना मिट्टी के हानिकारक रसायन रहित उच्च गुणवत्ता वाली स्वच्छ व ताजा सब्जियां उगेंगी।

इस प्रणाली में आम खेती की अपेक्षा पानी की जरूरत 90 प्रतिशत तक कम होती है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का इस्तेमाल करने में शुरुआत में अधिक लागत आती है, लेकिन दीर्घ अवधि तक खेती का लाभ ले सकते हैं। यह खेती शहरी क्षेत्रों के लिए काफी मददगार है।

प्रदेश के उपभोक्ता इंटरनेट पर बिता रहे हैं ज्यादा समय

फायदों के साथ नुकसान भी कम नहीं

स्क्रीन टाइम बढ़ने का मतलब है कि मोबाइल बार-बार देखा जा रहा है। ज्यादातर युवा रात को सोने का समय मोबाइल पर बिता रहे हैं। विशेषज्ञों व चिकित्सकों के मुताबिक लैपटाप व मोबाइल की ब्लू लाइट आंखों को नुकसान पहुंचाती है। अंधेरे में यह खतरा 4 गुना तक बढ़ जाता है। इससे आंखों की रोशनी भी जा सकती है।

डिजिटल के बढ़ते दायरे व नवाचारों के चलते प्रदेश के उपभोक्ता अब इंटरनेट पर ज्यादा समय बिता रहे हैं। राज्य में 6.32 करोड़ मोबाइल उपभोक्ताओं में से 76 फीसदी उपभोक्ताओं का इंटरनेट पर सर्फिंग व सर्च का समय बढ़ा है।

प्रदेश में हर तीसरे घर में इंटरनेट सुविधा है। इंटरनेट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कंटेंट स्ट्रीमिंग, ई-लर्निंग, इन्फोटेंनमेंट व सोशल मीडिया में हो रहा है। इससे स्क्रीन टाइम भी बढ़ गया है। कोरोना से पहले मोबाइल डेटा की खपत प्रति उपभोक्ता 5 जीबी थी। यह कोरोना के दौरान 10 जीबी डेटा तक पहुंच गई। अब यह खपत प्रति उपभोक्ता 15 जीबी तक पहुंच गई है।

राजस्थान में पहली बार है कि जब एक साल में ग्राफ इतनी तेजी से बढ़ा है। जयपुर शहर सहित राज्य में पिछले वर्ष अगस्त में 1.93 करोड़ जीबी मोबाइल डेटा प्रतिदिन खर्च हुआ, जो इस वर्ष फरवरी में बढ़कर 2.33 करोड़ जीबी पहुंच गया। इसके पीछे 5जी का बढ़ता उपयोग माना जा रहा हैं।

वैवाहिक कार्यक्रम हुआ ही नहीं, रिसोर्ट लौटाए जमा राशि

जयपुर स्थित अंबाबाड़ी निवासी विजय सोनी ने अपने बेटे के 10 दिसंबर से 12 दिसंबर 2020 तक होने वाले वैवाहिक कार्यक्रम के लिए 11 जुलाई 2020 को रिजेंटा रिसोर्ट व रॉयल ऑर्चिड होटल्स, रणथंभौर, सवाई माधोपुर को 1.1 लाख रुपए जमा कराए थे। लेकिन कोविड़ काल में पूरे देशभर में लॉक डाउन रहा और वैवाहिक कार्यक्रमों पर कई तरह के प्रतिबंध थे। कोविड प्रोटोकॉल के चलते सरकार ने आयोजनों पर कोई रियायत भी नहीं दी। इसके चलते रिसोर्ट में होने वाला कार्यक्रम उन्हें रद्द करना पड़ा। जब उन्होंने रिसोर्ट से अपनी जमा राशि वापस मांगी तो रिसोर्ट ने लौटाने का आश्वासन तो दिया लेकिन लौटाई नहीं।

हारकर उन्होंने रिसोर्ट के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग (द्वितीय) जयपुर में परिवाद दर्ज कराया और कहा कि जमा राशि नहीं लौटाना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस व सेवा दोष है। मामले की सुनवाई पर आयोग ने विजय सोनी के पक्ष में फैसला सुनाया। आयोग ने रिजेंटा रिसोर्ट व रॉयल ऑर्चिड होटल्स को उनकी जमा कराई राशि 1.1 लाख रुपए लौटाने का निर्देश दिया। साथ ही जमा राशि पर परिवाद दायर करने की तिथि 14 मार्च 2022 से नौ फीसदी ब्याज देने के लिए कहा है। आयोग ने सेवादोष होने पर रिसोर्ट पर 8,000 रुपए हर्जाना भी लगाया है।

निगरानी

राजस्थान पर है बजट से दोगुना कर्ज

देश के कई राज्यों में कर्ज व खर्च का संतुलन बिगड़ चुका है। राजस्थान समेत 10 बड़े राज्यों में 8 का हाल यह है कि इन पर बजट के मुकाबले कर्ज ज्यादा है। राजस्थान की बात करें तो वर्ष 2023-24 के लिए राजस्थान का बजट 2.33 लाख करोड़ रुपए है, जबकि कर्ज 5.30 लाख करोड़ रुपए है। फिर भी राज्य ने शिक्षा और सेहत के लिए सर्वाधिक धन आवंटित किया है।

चुनावी साल को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट के बाद भी कई बड़ी घोषणाएं और की गई है, जिनसे कर्ज भार और बढ़ेगा। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि यह सब कैसे होगा?

बैंक ऑफ बड़ौदा (मुंबई) के अर्थशास्त्री मदन सबनवीस कहते हैं-राज्यों के लिए बजटीय लक्ष्य हासिल करना बड़ी चुनौती होगा। इन्हें कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कद्दू' जयपुर